Closure of Industrial Units Belonging to Birlas, Bangurs and Goenkas Between 1980-1984

3369. SHRI CHHITTUBHAI GAMIT : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of industrial units of large and MRTP houses belonging to Birlas, Bangurs and Goenkas closed down between 1980 to 1984 giving the names of units and the number of workers affected thereby; and

(b) what specific steps have been taken by Central Government to reopen these units and the results thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : (a) In the Ministry of Labour, information is maintained only with regard to closures due to reasons other than industrial disputes. A statement on the number of such closures and workers affected for the years 1980-1983 is attached. Specific information relating to the number of large and MRTP units closed down during these years is not maintained.

(b) Does not arise.

Statement

Years	No. of Units Closed	Workers Affected
1980	338	18,164
1981	349	37,377
1982 (P)	286	26,602
1983 (P)	193	34,557

(P) = Provisional.

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

3370. **श्री कालीचरण शर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य को ब्याज की घटी दरों पर ऋण उपलब्ध करा कर सहायता न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री आरिफ मोहम्मद खां : (क) जी हां,

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम एक विकास वित्त संस्थान है और यह राज्य बिजली बोर्डों को जिन राज्यों में बिजली बोर्ड कार्य नहीं कर रहे हैं, उनमें राज्य सरकारों और राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के क्रियान्वय के लिए ग्रामीण बिजली सहकारिताओं को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता करता है। पिछड़े क्षेत्रों को दी गई ऋण सहायता की शर्तें अन्य क्षेत्रों की शर्तों की अपेक्षा अधिक उदार होती है।

ग्राम विद्युतीकरण निगम ग्रामीण बिजली सहकारिताओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा शेयर पूंजी में योगदान के लिए 2 से 5% के बीच सामान्य ब्याज की दर पर ऋण देता है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा पिछड़े क्षेत्रों और ग्रामीण बिजली सहकारिताओं के लिए उपलब्ध कराया गया रियायती वित्त पोषण का मध्य प्रदेश में काफी अधिक लाभ उठाया गया है। इस राज्य में अब तक 2441 लाख रु० की